शिमला से प्रकाशित

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 49 अंक-31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 22-29 जुलाई 2024 मूल्य पांच रूपये

वित्तीय से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है विश्वसनीयता का संकट

- अपने खर्चो पर लगाम लगाए बिना सारे आर्थिक उपाय अर्थहीन हो जाएंगे।
- कर्ज लेकर राहत बांटना भविष्य को गिरवी रखना है।
- व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र घातक होगा।

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से हिमकेयर योजना बन्द कर दी है। परिवहन निगम में न्यूनतम किराया बारह रुपये करने का फैसला लिया जा रहा है। रियायती येलो कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सम्मान कार्ड के रेट 50 रुपये से 100 रुपये कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों की स्कूल बसों के किराए में 50 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर दी है। सेवानिवृत कर्मियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत पर पुर्ननियुक्ति देने का फैसला लिया है। पिछली सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर कुछ राइडर लगा दिये हैं। महिलाओं को मिलने वाले 1500 पर भी कई शर्ते लगा दी है। इन्ही

फैसलों के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मुताबिक हर मंत्री को दो-दो व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है जो मन्त्री की छवि सुधारने के लिए काम करेंगे। सरकार ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए यह फैसले लिए हैं । इनके अतिरिक्त राजस्व में भी कई सेवाओं के दाम बढ़ा दिये हैं। सत्ता संभालते ही पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया था। पिछली सरकार द्वारा खोले गये करीब एक हजार संस्थान बंद कर दिए थे। सस्ते राशन के दामों में बढ़ौतरी के साथ उसकी मात्रा में कटौती भी कर दी गई है। कुल मिलाकर सरकार जहां संभव है सेवाओं और चीजों के दामों में बढ़ौतरी कर रही है। सरकार के इन फैसलों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी इस सब की परवाह किये बिना वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत हर माह करीब 1500 करोड़ का कर्ज लेने की स्थिति पहुंचने वाली है क्योंकि अब तक 25000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले चुकी है । यहां तक आशंका जताई जा रही है कि शायद कुछ माह बाद नियमित वेतन और पैन्शन का भुगतान कर पाने में कठिनाई आ जाये क्योंकि इस समय भी कई कर्मचारी वर्गो को नियमित न मिल पाने के मामले चर्चा में है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है।

सरकार को सत्ता में आये अठारह माह हो गये हैं और यह फैसले अब लिये जा रहे हैं। इसलिए यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर यह समझने में इतना समय क्यों लग गया? जबकि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो पहली बार ही विधायक बना हो। सबका लम्बा अनुभव है कई मुख्यमंत्रीयों का कार्यकाल देखा है। हर वर्ष सदन में बजट आता है । हर बजट में आर्थिक सर्वेक्षण आता है। हर वर्ष कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। यह वह दस्तावेज होते हैं जिनमें सरकार की सारी योजनाओं उसकी आय-व्यय और कर्ज का सारा रिकॉर्ड दर्ज रहता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर राजनीतिक पार्टियों चुनाव के लिए अपना-अपना घोषणा पत्र तैयार करती है और जनता में रखती है। कांग्रेस ने भी इसी आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार करके जनता को दस गारंटियां दी होंगी ऐसा माना जायेगा। फिर सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते ही चेतावनी दी थी कि प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबन्धन का आरोप लगाकर श्वेत पत्र तक लाया गया था। सरकार के वित्तीय नियंत्रण के लिये बाकायदा एफआरबीएम एक्ट पारित है। राजनीतिक नेतृत्व के लिए मंत्री परिषद के साथ ही अफसरशाही की भी एक बड़ी टीम सहयोग और कार्य संचालन के लिये उपलब्ध रहती है। जब भी सरकारें बदलती हैं तो नेतृत्व अपने अनुसार इस टीम में बदलाव करता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र के नाम पर इस टीम में लोकसभा चुनाव तक कोई बदलाव नहीं किया। जो अफसरशाही पिछली सरकार को चला रही थी वही इस सरकार में यथास्थिति बनी रही। बल्कि जिन लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कभी सदन में आरोप लगाये थे वही लोग सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं।

इसलिए यह कैसे संभव हो सकता है कि जिस प्रशासनिक तंत्र पर श्वेत पत्र में कुप्रबन्धन के आरोप लगे हो वही आज सर्वे सर्वा हो। व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र ने एक तरह से सरकार को स्वतः ही विश्वसनीयता के संकट पर लाकर

शेष पृष्ठ 8 पर.........

हिमकेयर बंदी कांग्रेस का एक और तुगलकी फ़रमान:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के प्राइवेट

अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड को बंद करने के निर्णय पर निराशा प्रकट करते हुए इसे जनहित के खिलाफ़ कांग्रेस का एक और तुगलकी फ़रमान बताया है। साल 2019 में भाजपा ने अपने कार्यकाल में हिमाचल में आयुष्मान भारत योजना से छूट गये लोगों को कैशलेस इलाज देने के लिये हिमकेयर योजना को शुरू किया था जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिल रहा था। सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज न मिल सकने की स्थिति में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकने की सुविधा जनता के लिए वरदान बनी थी मगर हिमाचल प्रदेश में जनता का सहारा बनी हिमकेयर योजना को कांग्रेस सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। अब हिमकेयर कार्ड धारक प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाएगा। इसके तहत पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज होता रहा है। हिमाचल व हिमाचल के बाहर 141 निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हिमकेयर कार्ड चलता था। सरकारी अस्पतालों व निजी अस्पतालों की संख्या 292 है, जहां ये हिमकेयर कार्ड की सुविधा मिलती आ रही थी मगर अपने आर्थिक कुप्रबंधन के चलते कांग्रेस ने भाजपा की एक और जनहित की योजना की बलि ले ली।

अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने मात्र ढ़ेड साल में 25000 करोड़ का कर्ज लेकर प्रदेश पर कर्ज का बोझ 95000 करोड़ पहुँचा दिया। कांग्रेस ने प्रदेश को दिया तो कुछ नहीं लेकिन यहाँ चल रहे स्वास्थ्य संस्थान, शिक्षा केंद्र, सरकारी स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली वर्दियां हों या मज़दूरों को मिलने वाली सुविधाएँ हों सब बंद करने का काम किया।

राज्यपाल ने विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रधानाचार्यों की कार्यशाला का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हमीरपुर के बणी में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रधानाचार्यो की चार दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्या भारती संस्थान का समाज के उत्थान में बहुमूल्य योगदान रहा है। यहां से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यशाला में 500 से अधिक प्रधानाचार्यो ने भाग लिया।

राज्यपाल ने कहा कि विद्या भारती की नींव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रखी गई थी और इसका विस्तार कई शहरों तक हो चुका है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा तंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, वहीं विद्या भारती भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन को प्रोत्साहित कर रही है। विद्या भारती से जुड़े शिक्षक समर्पित भाव के साथ परिर्वतनकारी और प्रगतिशील शिक्षा तंत्र बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्या भारती ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन होने के नाते विद्या भारती द्वारा देश में हजारों विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है और ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि विद्या

भारती वर्ष 1952 से बिना सरकारी सहायता के बेहद उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में विद्यार्थियों का समग्र विकास हो रहा है और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी जागृत की जा रही है। श्री शुक्ल ने कहा कि विद्या भारती ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर अच्छी पहल की है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय पाठयक्रम 2023 देश में शिक्षा की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए माहौल पैदा करना, उन्हें 21 वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना और उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और दृढ़ता लाना हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि नए पाठयक्रम को सफलतापूर्वक लागू करना शिक्षकों के नेतृत्व की क्षमता, उनके दृष्टिकोण और समर्पण पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय पाठयक्रम के परिवर्तनकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक एक निर्णायक भूमिका में हैं, ताकि वह कक्षा में इसे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और अर्थपूर्ण अनुभव बना सकें।

उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि एक जीवंत, समावेशी और क्रियाशील शिक्षा तंत्र बनाएं, ताकि हर विद्यार्थी अपने संभावित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस दौरान राज्यपाल ने विद्या भारती द्वारा प्रकाशित भारत की समृद्ध संस्कृति को प्रस्तुत करती पुस्तकों का भी विमोचन किया।

इससे पूर्व, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्रि देशराज शर्मा ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।

सेवन स्टार इंटरनेशनल स्कूल बणी के प्रबंध निदेशक संदीप कंवर ने राज्यपाल को सम्मानित किया। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय नड्डा, हिमाचल प्रांत के महामंत्री सुरेश कपिल और सेवन स्टार इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक संदीप कंवर ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। इस दौरान स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ कर से छूट:उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ कर स्पेशल रोड टैक्स से छूट प्रदान की है। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट के तहत कवर नहीं हैं को अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन विभाग द्वारा बागवानों और किसानों के उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेब और आलू के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से छूट प्रदान करने से सभी हितधारकों को मदद मिलेगी।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानसून तथा सेब सीजन के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण की गई हैं। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी एहतियाती उपाय पूर्ण किए गए हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 29वीं बैठक में 25 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान

शिमला। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 29वीं बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 25 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें लगभग 2216.93 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 5,027 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए नए प्रस्तावों में निम्नलिखित इकाइयां शामिल हैं:-

टैबलेट्स एवं कैप्सूल के उत्पादन के लिए मैसर्ज प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, गांव मखनुमाजरा, बद्दी जिला सोलन, जूस कंसन्ट्रेट के प्रसंस्करण और इंटिग्रेटिड कोल्ड एटमॉसफेरिक स्टोरेज उत्पादन के लिए मैसर्ज एग्जॉटिक फ्रूट्स कुमारसैन जिला शिमला, लिक्विड वायल लायोफिलाइजर, एम्पुल लाइन आदि के उत्पादन के लिए मैसर्ज पोटेंट बायोटेक लिमिटेड गांव बेलीदेयोर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, सेब जूस कंसन्ट्रेट, विनैगर, वाइन, पेस्टिन के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड शिमला ठियोग, माल्ट स्पिरिट के उत्पादन के लिए मैसर्ज वीकेएम लिकर एलएलपी, गांव बोहलियो जोगिबन, जिला सिरमौर, टैबलेट और कैप्सूल के उत्पादन के लिए मैसर्ज स्माइलैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र, पलसारा, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, माल्ट स्पिरिट और आईएमएफएल सीएल बॉटलिंग के उत्पादन के लिए मैसर्ज एडीएस स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड गांव फंडी बोदीवाला, उप-तहसील माजरा, जिला सिरमौर, प्रीफिल्ड सिरिंज, टैबलेट और कैप्सूल के उत्पादन के लिए मैसर्ज रिशलेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र मंझोली, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, आईएमएफएल के उत्पादन के लिए मैसर्ज उब्बू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र अंब, तहसील अंब, जिला ऊना, पफ पैनल, दरवाजे व खिड़कियों के निर्माण के लिए मैसर्ज जियाना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मंडयारपुर किरपालपुर तहसील नालागढ़ जिला सोलन और टैबलेट, कैप्सूल, तरल पदार्थ, मलहम आदि के उत्पादन के लिए मैसर्ज अलवेंटा फार्मा लिमिटेड यूनिट-2 औद्योगिक क्षेत्र किरपालपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन शामिल हैं।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विस्तार प्रस्तावों में निम्नलिखित इकाइयां शामिल हैं:-

क्लिंकर, सीमेंट, ऊर्जा उत्पादन के लिए मैसर्ज अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड गांव सुली, तहसील अर्की, जिला सोलन, लेखन और मुद्रण सामग्री के निर्माण के लिए मैसर्ज रुचिरा पेपर्स लिमिटेड कालाअंब, जिला सिरमौर, क्लिंकर और विद्युत उत्पादन के निर्माण के लिए मैसर्ज अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, गांव रौड़ी, तहसील अर्की, जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड बोतलों आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज आयोसिस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड, गांव खेड़ा निहला, डाकघर और तहसील नालागढ़, जिला सोलन, प्रोसेस्ड फैब्रिक, ग्रिज फैब्रिक आदि के उत्पादन के लिए मैसर्ज ऑरो टेक्सटाइल्स, साई रोड बद्दी, जिला सोलन, टफन्ड ग्लास इंसुलेटेड लेमिनेटिड ग्लास आदि के निर्माण के लिए मैसर्ज थर्मोसोल ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, काला अंब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर शामिल हैं।

टैबलेट, मीटर्ड डोज इन्हेलर, मलहम इत्यादि के उत्पादन के लिए मैसर्ज ऑक्सालिज़ लैब्स, गांव ठेड़ा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, नेजल स्प्रे, आई ड्रॉप इत्यादि के उत्पादन के लिए मैसर्ज माया बायोटेक, गांव कौंडी, तहसील बद्दी, जिला सोलन, टैबलेट, हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, लिक्विड सिरप इत्यादि के उत्पादन के लिए मैसर्ज मैकलियोड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गांव ठेड़ा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, एम्पाउल्स, शीशी, आई-ईयर-ड्रॉप्स और अन्य इंजेक्टेबल उत्पादों के उत्पादन के लिए मैसर्ज मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, गांव किशनपुरा, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, पीवीसी इन्सुलेटिड वायर केबल्स इनवर्टर और यूपीएस के निर्माण के लिए मैसर्ज माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-1, प्लॉट नंबर, 12, परवाणु जिला सोलन, टैबलेट, कैप्सूल एवं लिक्विड आदि के उत्पादन के लिए मैसर्ज केचौट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गांव थाना, तहसील बद्दी, जिला सोलन, प्रोसेस्ड फैब्रिक, ग्रिज और डाइड फैब्रिक, प्रिंट प्रोसेस्ड फैब्रिक आदि के उत्पादन के लिए मैसर्ज ऑरो टेक्सटाइल्स वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड की एक इकाई साई रोड बद्दी, जिला सोलन, प्रोटीन पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड सिरप और सस्पेंशन के उत्पादन के लिए मैसर्ज तिरुपति लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, सूरजपुर, पांवटा साहिब, सिरमौर शामिल हैं।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नज़ीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, विशेष सचिव बहु-उद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा अरिंदम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में 108 एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी और 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी एम्बुलेंस को शीघ्र बदला जाए और उनके स्थान पर नई एम्बुलेंस खरीदकर लोगों को निर्बाध सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही कंपनी को निर्देश दिए कि समझौता ज्ञापन के अनुसार पुरानी एम्बुलेंस वाहनों को शीघ्र बदला जाए तथा उनका रखरखाव भी गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए।

उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस के लिए लोगों द्वारा की गई कॉल पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन सेवाओं का लाभ प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों सहित सभी लोगों को सुनिश्चित हो।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, एनएचएम की मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही कंपनी के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के युवा अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों से हो रहे हैं प्रशिक्षित: राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने खलीनी स्थित टीसीआईएल प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। वर्तमान में इस केंद्र में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत रोबोटिक्स, एसक्यूएल, वीबी स्क्रिप्ट, पायथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न उन्नत पाठयक्रमों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस केन्द्र में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रायोजित इन पाठयक्रमों के 35 प्रशिक्षुओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल को निखारने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के युवाओं को उद्योगोन्मुखी आधुनिक पाठयक्रमों का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है और रोजगार उपलब्ध करवाने वाले आधुनिक पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार की तलाश में भटकने के बजाये उन्हें रोजगार प्रदाता के रूप में उभरने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

संस्थान में प्रशिक्षुओं की कम उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशिक्षण माहौल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम के अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण केन्द्रों का दौरा करने और संस्थानों का रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च मानकों को बनाये रखना नितांत आवश्यक है, ताकि प्रशिक्षु गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत कर प्रशिक्षण संबंधी उनके अनुभव भी जानें।

इस अवसर पर निगम के महाप्रबंधक नरेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वन निगम को अपने डिपो में रखी ईमारती लकड़ी की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 214वीं निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई ईमारती लकड़ी की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि इसे गलने से बचाया जा सके। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के प्रथम चरण की मंजूरी के उपरांत रेखागत परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन मंडल अधिकारियों डीएफओ सहित निगम के अधिकारियों को शक्तियां सौंपने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार एफसीए मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने निगम को दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करने तथा भविष्य में निविदाओं में उनके भाग लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आठ करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 10.04 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। उन्होंने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 100 वन वीरों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार वन निगम को आत्मनिर्भर और लाभप्रद बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

निदेशक मंडल ने 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की, जिससे 227 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में निगम के दैनिक भोगियों की दिहाड़ी 400 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, निगम के सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने तथा दो वर्ष का अनुबन्ध कार्यकाल पूरा करने वाले 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले वर्ष मॉनसून के प्रकोप के कारण शिमला शहर में 618 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी लकड़ी बेचकर 2.50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

इस मौके पर वन निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51 लाख रुपये का चेक भेंट किया।

वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, प्रधान सचिव वन अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल राजीव कुमार व अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों के विलय की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2003 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जहां विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख 30 हजार 466 थी वहीं वर्ष 2023-24 में यह संख्या घटकर 49 हजार 295 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। उन्होंने कहा कि 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र पांच है और इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से दो किमी के दायरे में स्थित हैं। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है। इसके अलावा 46 मिडल स्कूल तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालातों के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों को विलय करने की संभावनाएं तलाश की जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को विलय करने के कदम से पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकेगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ-साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे वे राष्ट्र के सशक्त नागरिक बनेंगे।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर व स्पीति में दो पूर्ण सुसज्जित बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने शिक्षा विभाग को संबंधित क्षेत्रों में इन बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए।

सुक्खू ने कहा कि स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने क्लस्टर बनाए हैं तथा स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों के लिए अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने का विकल्प दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों में मानकों को बढ़ाने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम भी लागू किया है।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा आशीष कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

आम बजट में हिमाचल प्रदेश की बड़ी अनदेखी:राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने देश के 2024-25 के आम बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा ने यह बजट अपने गठबंधन सहयोगियों को खुश करने व प्रधानमंत्री की कुर्सी पक्की करने के लिये बनाया गया लगता है। उन्होंने कहा है कि बजट पूरी तरह दिशाहीन है जिसमें न तो बढ़ती महंगाई रोकने के कोई उपाय है और न ही बढ़ती बेरोजगारी कम करने की कोई ठोस योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी इस बजट में मजबूत योजना का उल्लेख नही है।

कुलदीप सिंह राठौर ने संसद में प्रस्तुत आम बजट को महज आंकड़ो का दस्तावेज बताते हुए कहा है कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश की बड़ी अनदेखी की गई है। आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश का बजट में राहत देने का उल्लेख तो किया गया है पर यह स्पष्ट नही है कि यह राहत कितनी व किस रूप में दी जाएगी, जबकि आपदा से प्रदेश को 12 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की विकट आर्थिक स्थिति के चलते प्रदेश को किसी आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी,जो धरि की धरी रह गई। प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

राठौर ने कहा कि प्रदेश के बागवानों विशेष तौर पर सेब उत्पादकों को इस बजट से घोर निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि विदेश से आने वाले सेब पर आयात शुल्क शत प्रतिशत किया जाएगा पर ऐसा कुछ नही हुआ। इसी तरह किसानों को भी राहत के नाम पर इस बजट में सब्जबाग दिखाने की कोशिश की गई है पर देश के किसान भाजपा की नीति व नियत से भली भांति परिचित है।

राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा का दोहरा चरित्र सबके सामने है। विहार व आंध्रप्रदेश की अपनी सहयोगी सरकारों को खुश करने के लिये इन्हें आर्थिक पैकेज जारी किए गए है जबकि कांग्रेस व गैर भाजपा शासित राज्यों की बजट में पूरी तरह अनदेखी की गई है।

मुख्यमंत्री ने विश्व पैराग्लाडिंग कप की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खु ने कांगड़ा ज़िले के बीड़-बीलिंग में 2 से 9 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले विश्व पैराग्लाडिंग कप-2024 की आधिकारिक वेबसाइट का आज यहां से शुभारंभ किया। वेबसाइट में विश्व कप से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक में हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा विश्व कप का आयोजन बीलिंग पैराग्लाडिंग एसोसिएशन के सहयोग से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। यह हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में 50 देशों के 130 पायलट इस चुनौतीपूर्ण और रामोचंक प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। पैराग्लाडिंग के लिए बीड़ बीलिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थल है। उन्होंने कहा कि धौलाधार श्रृंखला के साथ यहां प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए बहुत मनोरम नजारा देखने को मिलेगा और यह प्रतियोगिता उनके लिए अविस्मरणीय बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार साहसकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। हिमाचल अपने पहाड़ी परिदृश्य, अनुकूल मौसम व प्राकृतिक सुंदरता के चलते पैराग्लाडिंग प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। वर्तमान प्रदेश सरकार पैराग्लाडिंग के आयोजनों के लिए पूरी सुवधिाएं देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पैराग्लाडिंग उत्सव में भारत की समृद्ध संस्कृति, कला, साहसिक खेलों, साहित्य और मनोरंजन से रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा। पैराग्लाडिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए विश्वस्तरीय शुभारम्भ और समापन समारोहों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है जो राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। कांगड़ा ज़िले को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है और यहां पर आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए अनुभव यादगार बने।

उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पांच हेलीपोर्ट के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं शिमला का संजौली एयरपोर्ट जल्द ही तैयार होने जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलापुर के गोविंदसागर और ऊना के अंदरौली में जलक्रीड़ा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पौंग बांध में गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ान जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। इसके अलावा, पर्यटन सीजन के दौरान दुकानों को 24 घंटे खुली रखने की छूट देने का भी फैसला किया गया है।

बीलिंग पैराग्लाडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि विश्व पैराग्लाडिंग कप केवल खिलाड़ियों की छिपी प्रतिभा को ही प्रदर्शित नहीं करेगा बल्कि यहां की मनोरम सुंदरता और साहसिक अवसरों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी और नवाचार गोकुल बुटैल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट इस मौके पर उपस्थित थे जबकि पैराग्लाडिंग विश्व कप एसोसिएशन के अध्यक्ष और पैराग्लाडिंग विश्व कप के प्रतियोगिता निदेशक गोरन दिमिशकोवस्की वर्चुअल रूप से जुड़े।

राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस, आईटीबीपी, एनसीसी, होमगार्ड एवं एसएसबी मेडिकल सेंटर के प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मास्टर प्रशिक्षकों के तौर पर एचआईवी/एड्स के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि सभी मास्टर ट्रेनर संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में एचआईवी/ एड्स विषय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान कर सकें।

उन्होंने कहा कि एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रतिवर्ष 30 से 40 मास्टर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस, आईटीबीपी, एनसीसी, होमगार्ड एवं एसएसबी के सभी जवानों को एचआईवी/एड्स बारे विस्तृत जानकारी प्रदान कर उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा, ताकि वह समाज में इस विषय पर सही जानकारी का प्रचार-प्रसार कर जागरूकता ला सकें।

परियोजना निदेशक ने बताया कि समिति के जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों में भी कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाता है।

कभी मत सोचिये कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है, तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं।

...... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

नीति आयोग का बहिष्कार क्यों?

नीति आयोग का गठन केन्द्र सरकार ने 2015 में योजना आयोग के पूरक के रूप में किया है। भारत सरकार का यह सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। यह संस्थान भारत की राज्य सरकारों को इसमें शामिल करके आर्थिक विकास और सरकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये काम करता है। इसके उद्देश्य में सात वर्षीय विभिन्न रणनीति, पन्द्रह वर्षीय रोड मैप और कार्य योजना, अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इन्नोवेशन मिशन और चिकित्सा शिक्षा सुधार और कृषि सुधार शामिल हैं। प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित राज्यों के उप-राज्यपाल तथा कुछ विषय विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। अभी केन्द्र का बजट आने के बाद नीति आयोग की बैठक बुलाई गयी थी। कांग्रेस समेत विपक्ष ने इस बैठक के बहिष्कार का फैसला लिया क्योंकि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को नामत कुछ आर्थिक आबंटन हुआ है। बाकी राज्यों को नामत कोई आबंटन न होने से बहिष्कार का फैसला लिया गया। लेकिन ममता इस फैसले के बावजूद बैठक में शामिल हुई और बीच में ही उठकर चली गयी। यह आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। विपक्ष ने सामूहिक रूप से समय न दिये जाने की निंदा की है। परन्तु कांग्रेस के ही अधीरंजन ने ममता को झूठी करार दे दिया। इसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बजट से पहले दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री से मिले थे। इन मुलाकातों में प्रदेश के लिये आर्थिक सहायता की मांगे रखी गयी थी। इन मुलाकातों के बाद बजट आया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में खुलासा किया है कि केंद्रीय बजट में प्रदेश को 13351 करोड़ मिले हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों, सुरंगों और रेलवे विस्तार के लिये प्रदेश को एक मिले आबंटन की डिटेल रखी गयी है। केंद्रीय राज्य मंत्री के दावे के मुख्य मन्त्री के प्रधान सलाहकार मीडिया ने रश्मि तौर पर सवाल उठाये हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय फैसले के तहत नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। लेकिन इसी मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ मीट के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शिरकत की थी जबकि कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुये थे। तब इस शामिल होने को प्रदेश हित करार दिया गया था। निश्चित तौर पर नीति आयोग की बैठक का आयोजन भोज के आयोजन से प्रदेश हित में एक बड़ा अवसर था। प्रदेश के भविष्य का सवाल था। इस बैठक में शामिल होकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति का सर्वोच्च नीति थिंक टैंक के फोरम पर आधिकारिक तौर पर विवरण रखा जा सकता था लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नीति आयोग योजना आयोग के पूरक के रूप में एक सर्वोच्च नीति निर्धारण मंच है। इस मंच पर प्रदेश की समस्याओं का आधिकारिक रूप से रखा जाना आवश्यक था। क्योंकि सुक्खू सरकार को सत्ता में आये डेढ़ वर्ष का समय हो गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की जनता को दस गारंटीयां दी गया थी। यह गारंटीयां देते हुये कोई किन्तु-परन्तु नहीं लगाये गये थे। सरकार के गठन के साथ ही मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों और उसके बाद कैबिनेट रैंक में सलाहकारों और विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिनसे यह कतई संदेश नहीं जाता कि प्रदेश में वित्तीय संकट है। लेकिन आज जिस तरह से जनता को पहले से मिले आर्थिक लाभों पर कैंची चलाई जा रही है उससे यह संदेश गया है कि सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। लेकिन अब तक के कार्यकाल में ही जितना कर्ज ले लिया गया है उस गति से कार्यकाल के अन्त तक यह आंकड़ा पूर्व सरकारों द्वारा लिये गये कर्ज के आंकड़े से भी बढ़ जायेगा। इसलिये आज कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प बनने के लिये अपनी सोच और कार्यशैली दोनों पर पुन:विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय कांग्रेस की राज्य सरकारों की परफॉरमैन्स पर जनता अपना एक स्पष्ट मत बना पायेगी। क्योंकि इस समय हिमाचल की सरकार की कार्य प्रणाली से यह संदेश नहीं जा पा रहा है कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार वास्तविक रूप से भगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर भाजपा ने क्या किया?

गौतम चौधरी

विगत लगभग एक महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को उठा रही है। भाजपा का कहना है कि 1951 से लेकर 2011 तक झारखंड में सनातनी हिन्दू और आदिवासियों की जनसंख्या घट गयी है। भाजपा के नेता लगभग प्रति दिन अपने प्रेस ब्यान और संवाददाता समेलनों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका मानना है कि झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठियों का रणनीतिक पनाहगाह बन गया है। उनका आरोप यह भी है कि वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार प्रदेश में बांग्लादेशी घुसवैठियों के प्रति उदार भाव रखती है। यही कारण है कि इधर के दिनों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहां आना बढ़ गया है। इस संदर्भ में एक मामला झारखंड उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। कायदे से उस पर सुनवाई भी हो रही है। विगत दिनों माननीय न्यायालय ने झारखंड के कई जिला उपायुक्तों को यह सबक दिया कि वे अपने-अपने जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची बनावे और उसे न्यायालय में दाखिल करें। हालांकि, कई आधिकारिक मंचों से झारखंड सरकार, उसके मंत्री और अधिकारियों ने बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे किसी प्रकार की समस्या को नकारती रही है लेकिन भाजपा लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है।

सच पूछिए तो झारखंड भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। या ऐसा कहें कि झारखंड भाजपा को मुख्यमंत्री हेमंत और उनके रणनीतिकारों ने दिशाहीन बना दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या यदि इतनी ही जटिल और भयावह होती तो झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक साढ़े 13 वर्षों तक प्रदेश में किसी न किसी रूप में भाजपा शासन में रही है। यदि भाजपा इस मामले को लेकर ईमानदार होती तो वह अपने शासनकाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किए गए कारवाई के बारे में कुछ न कुछ बताती। क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी खुद कहते हैं कि वर्ष 1951 से लेकर आजतक बांग्लादेशियों का घुसपैठ जारी है।

दूसरी बात यह है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जब भाजपा में नहीं थे तो उन्होंने कई अवसरों पर यह कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई समस्या नहीं है। यही नहीं, एक खास भाजपा सूत्र का तो यहां तक कहना है कि जब प्रदेश में रघुवर दास की सरकार थी तो उस समय कई हिन्दूवादी संगठन और भाजपा के कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री दास को बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात कही लेकिन वे नकार गए।

इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि भाजपा जब-जब सत्ता से बेदखल होती है और चुनाव का वक्त आता है, तो भाजपा नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या याद आती है। भट्टाचार्य या फिर कांग्रेस के प्रवक्ताओं का तर्क है कि घुसपैठ अंतरराष्ट्रीय सीमा से होता है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और सीमा सुरक्षा बल, जिस मंत्रालय के पास है और जो घुसपैठियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है उस गृह मंत्रालय की जिम्मेबारी अमित शाह के पास है। घुसपैठ यदि हो रहा है तो केन्द्रीय गृहमंत्रालय उसके आंकड़े राज्य सरकार को साझा करे। फिर राज्य सरकार उस पर कारवाई करेगी। भट्टाचार्य राजनीतिक ब्यान देने में माहिर हैं लेकिन यह तर्क उनका ठीक है। घुसपैठ को रोकना या फिर घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना अकेले राज्य सरकार के बूते की नहीं है। इसके लिए केन्द्र सरकार को भी सहयोगी रवैया अपनाना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश भाजपा को पहले केन्द्रीय गृहमंत्रालय पर दबाव बनाना चाहिए। यह काम बिना उसके सहयोग से संभव नहीं है।

भाजपा का डेमोग्राफी में बदलाव वाला तर्क सही जान पड़ता है। यह साफ तौर पर झलक रहा है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में जिस प्रकार से एक खास वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है वह चिंता का विषय है लेकिन सवाल यह उठता है कि अपने समय में भाजपा ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया?

अंत में एक बात और समझनी चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल राज्य सरकारों की सक्रियता से ही संभव नहीं है। मान लीजिए राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया फिर उसका क्या होगा? विगत 10 वर्षों से भाजपा केंद्र की सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। कई बार नरेंद्र मोदी की मुलाकात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से हुई है। एक बार भी मोदी ने हसीना के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर बात नहीं की।

यहां यह भी बता दें कि जब असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा अभियान चल रहा था उस समय बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से एक आधिकारिक ब्यान आया था, जिसमें बताया गया था कि घुसपैठियों को वापस लेने से संबंधित भारत सरकार के साथ उनकी सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है और आगे भी ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि यह मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है।

ऐसी परिस्थिति में झारखंड भाजपा या भाजपा के कोई केन्द्रीय नेता बांग्लादेशी घुसपैठ पर किसी प्रकार की कोई बात करते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? इसका साफ संदेश यह है कि यह मामला केवल राजनीतिक है। इससे प्रति भाजपा का नेतृत्व भी गंभीर नहीं है। एक केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, न कि समस्या के समाधान के लिए।

कुल मिलाकर, झारखंड का वर्तमान भाजपा नेतृत्व मुद्दे और रणनीतियों को लेकर विभ्रम की स्थिति में है। डीलिस्टिंग पर भाजपा का कोई स्थाई चिंतन नहीं है। खुद बाबूलाल आदिवासी को हिन्दू नहीं मानते हैं। 1932 के खतियान के मामले में प्रदेश भाजपा का कोई स्टैंड नहीं है। पेसा कानून पर प्रदेश भाजपा मौन साधे हुए है। ऐसे में भाजपा का विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या-क्या होगा यह किसी को पता नहीं है। नेतृत्व के संभ्रम और रणनीति विहीनता की स्थिति में प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ना तय किया है। संभवत: झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा राष्ट्रीय मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी क्योंकि प्रदेश में उसके पास कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है।

कारगिल विजय दिवस के शहीदों को नमन

देश में राष्ट्रभक्ति का गज़ब का माहौल था ऐसा लगता था सारा भारत एक है, देश की एकता, अखण्डता, सर्वभौमिकता बचाये रखने के लिये कुछ भी कर गुजरने को तैयार था । कारगिल का संघर्ष क्या शुरू हुआ ऐसा लगा जैसे सारा राष्ट्र और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक देश के लिये कोई भी कुर्बानी देने को तैयार था ।

विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ जब देशभक्ति से ओत-प्रोत विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के प्रधानमन्त्री, अटल जी सभी चुनौतियों, चेतावनियों और व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरों को नज़र अन्दाज करते हुये 2 जुलाई 1999 को सीमा पर तैनात युद्धरत सैनिकों की पीठ थपथपाने के लिये स्वयं सीमा पर जा पहुंचे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमन्त्री को अपने साथ सीमा पर खड़ा देखकर सैनिकों का साहस तो सातवें आसमान पर पहुंचना स्वभाविक था।

5 जुलाई 1999 को कारगिल के युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद श्रीनगर के सैनिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल सैनिकों को दैनिक उपयोग का आवश्यक सामान दे रहे थे, एक जवान चादर ओढ़े हुये लेटा था उसने सामान पकड़ा नहीं, हमने बिस्तर के साईड टेबल पर सामान रखा और आगे बढ़ने लगे तभी डॉक्टर ने कहा कि माईन ब्लास्ट में इस वीर सैनिक के दोनों हाथ और दोनों पैर चले गये थे । हम फिर मुड़े और पूछा, ''बहुत दर्द होता होगा'', सैनिक ने उत्तर दिया, ''कल शाम से नहीं हो रहा

है'' । हमने पूछा क्या कोई (पेन किलर) दर्द निवारक दवाई ली या टीका लगा? उसने उत्तर दिया ''नहीं, कल शाम (4 जुलाई को) टाईगर हिल वापस ले लिया और तिरंगा फहरा दिया, मेरा दर्द चला गया। राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को शत शत नमन।

आजकल एक और विवाद मीडिया में देखने को मिला यहां शहीद की नौजवान विधावा ने मरणोपरान्त मिलने वाले सम्मान को शहीद के मॉं-बाप के साथ सांझा करना उचित नहीं समझा। ऐसी समस्यायें आप्रेशन विजय के बाद भी आई थीं, अधिकतर विधवायें नवविवाहिता थीं और उनका पुनर्विवाह होना स्वाभाविक और न्यायोचित भी था परन्तु बुजुर्ग मॉं-बाप का सहारा भी तो शहीद जवान ही होता था इसलिये पुनर्विवाह के समय प्रदेश और केन्द्र सरकार की ओर से मिली सारी की सारी अनुदान राशि, पैट्रोल पम्प या गैस एजैन्सी आदि सभी को साथ ले जाना मॉं-बाप के साथ अन्याय था क्योंकि अधिकतर मामलों में गरीब मॉं-बाप ने अपना पेट काट कर बेटे को पाला पोसा होता था और बुढ़ापे में नौजवान बेटे की शहादत और बहु का सब कुछ अपने साथ ले जाना उनके लिये दोहरा अघात होता था।

इसलिये हमने प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया कि अगर तो पुनर्विवाह उसी परिवार में होता है तो सभी कुछ वैसे ही रहेगा लेकिन यदि वीर नारी कहीं दूसरी जगह शादी करती है तो सरकार की ओर से मिली राशि दो हिस्सों बांट दी जायेगी। आधी राशि उस युद्ध विधवा को और आधी राशि बूढ़े मॉं-बाप को दी जायेगी और यदि शहीद के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और मॉं तथा दादा-दादी से अलग रहते हों तो राशि तीन भागों में बांटी जायेगी और एक तिहाई बच्चों को दी जायेगी। इस निर्णय से सभी की समस्या का समाधान हो गया ।

राष्ट्रभक्ति के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्वेदनशीलता के भी कई उदाहरण देखने को मिले, शिमला जिले का एक अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाला जवान शहीद हुआ था, घर की अर्थिक स्थिति भी कमजोर थी । जब हमने अनुग्रह राशि उन्हें दी तो उस गरीब परिवार ने कहा हमें आधी राशि ही दीजिए, अभी युद्ध चल रहा है और शहीद हो रहे हैं और आपको कई और परिवारों की सहायता करनी है, हमें आधी राशि दे दो बाकि किसी और परिवार के काम आ जायेगी। शहीद की शहादत को तो नमन था ही पर गरीब परिवार की सम्वेदनशीलता और दूसरों के प्रति समर्पण की भावना से हम सभी द्रवित हो गये और उन्हें धन्यवाद देते हुये हमने कहा कि राशि आपके लिये ही है और आवश्यकता होगी तो लोग योगदान दे ही रहे हैं ।

पालमपुर में तो जहां एक ओर प्रथम परमवीर चक्र विजेता, मेजर सोमनाथ शर्मा वहीं कारगिल युद्ध के नायक कै. विक्रम बतरा, परमवीर चक्र विजेता का भी घर है, उस दिन हम कै. विक्रम बतरा के पार्थिव शरीर का इन्तजार कर रहे थे वहीं पर कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद कै. सौरभ कालिया की माता जी, श्रीमति विजय कालिया और कै. विक्रम बतरा की माता जी साथ साथ बैठी थीं। श्रीमति विजय कालिया श्रीमति बतरा को ढांढस बंधा रही थीं, एक महान मां दूसरी महान माता को साहस बंधा रही थी, शायद यही जीवन है।

इसी प्रकार जिला बिलासपुर की एक बहादुर मां, श्रीमति कौशल्या देवी जी जब मिली तो उन्होंने कहा, ''धूमल जी कल मंगल सिंह की अर्थी को डेढ किलो मीटर मैंने कंधा दिया''। मैंने पहली बार सुना कि शहीद की मॉं ने अपने शहीद सुपुत्र की अर्थी को कंधा दिया हो। शहीद की शहादत और मॉं की हिम्मत को सलाम।

सोलन जिला मुख्यालय में चपरासी के पद पर नियुक्त एक व्यक्ति का सैनिक बेटा शहीद हो गया, अन्तिम संस्कार में भाग लेने के बाद हम उसके घर ढांढस बंधाने के लिये गये। शहीद की मॉं ने कहा मेरा बेटा देश के काम आ गया, दूसरा बेटा दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है यह भी पढ़कर फौज में भर्ती होगा और देश की सेवा करेगा।

जिला हमीरपुर के बमसन क्षेत्र में पहाड़ी के ऊपर एक बगलू गांव है यहां से राज कुमार सुपुत्र श्री खजान सिंह शहीद हुये थे । चढ़ाई चढ़ते मैं सोच रहा था कि शहीद के बजुर्ग पिता जी से कैसे बात करूंगा । मैं उनके आंगन में पहुंच गया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, श्री खजान सिंह बोले, ''धूमल साहब, बेटे तो पैदा ही इसलिये किये जाते हैं कि पढ़ें, लिखें और बड़े होकर फौज में भर्ती हों और देश की रक्षा करें। उन्होंने अपने दोनो पोते मुझे मिलाये और कहा ये भी पढ़कर फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने मुझे कहा आप दिल्ली जायेंगे तो प्रधानमन्त्री, वाजपेयी जी को कहना कि जवानों की यदि कमी हो तो 82 वर्ष का हबलदार खजान सिंह आज भी हथियार उठाकर देश की रक्षा करने के लिये तैयार है।

शहीदों का आदम्य साहस, परिवारों का सम्पूर्ण समर्पण, अटल जी का दृढ़निश्चयी नेतृत्व सदियों तक देश के लिये प्रेरणा रहेगा।

5 जुलाई को जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आदरणीय अटल जी को फोन करके कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ इनके पास पहुंच गये हैं और अटल जी से आग्रह किया कि वे भी युद्ध विराम की घोषणा कर दें और अमेरिका आ जायें ताकि समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जा सके ।

उस ऐतिहासिक क्षण में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन ''जब तक एक भी घुसपैठिया कारगिल में है, तब तक न युद्ध विराम होगा और न मैं देश छोड़कर कहीं जाऊंगा'' इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ।

प्रधानमन्त्री के इस दृढ़संकल्प को देखते हुये सारे राष्ट्र में एक नई ऊर्जा आ गई और सैनिकों में यह संकल्प और दृढ़ हो गया और भारत की वीर सेना ने निर्णायक विजय प्राप्त की ।

कारगिल से वापसी पर हम प्रभु अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास उतरे, दर्शन किये और संयोग से टाईगर हिल विजय प्राप्त करने वाले जवान भी उसी समय गुफा में दर्शन करने के लिये आये हमने उन से चर्चा की और श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो उनके हथियार लेकर उन हथियारों के बारे में जानकारी भी ली ।

यह उचित ही है कि 26 जुलाई को प्रतिवर्ष हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और उन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ठीक ही कहा है ''शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशां होगा''।

प्रेम कुमार धूमल
पूर्व मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना से आएगी किसानों के जीवन में खुशहाली

शिमला। हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि और कृषि संबंधित कार्यों से आजीविका अर्जित करती है। मेहनतकश किसान खून-पसीना बहाकर खेतों से सोना उगाते हैं। अन्नदाता को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अनेक महत्त्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं।

प्रदेश सरकार की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना किसानों की आय में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त करेगी। योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायनमुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगभग 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना से जुड़ने वाले किसानों द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार गेहू को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। देश में गेहूं और मक्की पर दिया जाने वाला यह सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा।

किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रदेश सरकार की मुहिम रंग ला रही है। वर्तमान में प्रदेश के 1,78,643 किसान-बागवान परिवारों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है। प्रदेश में 24,210 हेक्टेयर भूमि पर इस विधि से खेती की जा रही है और चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के 9.61 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-2024 में 1275.31 लाख रुपये व्यय कर 37,087 किसानों को लाभान्वित किया गया और 13,176 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक भूमि के अधीन लाया गया है। प्राकृतिक खेती उत्पादों की बिक्री के लिए 10 मंडियों में स्थान निर्धारित कर आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

किसान एवं उपभाक्ताओं के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नवोन्मेषी पहल की गई है। इस पहल के तहत www.spnfhp.in के तहत अभी तक प्रदेश के 76,000 से अधिक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है और 74,283 किसानों-बागवानों को प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं। यह प्रमाणीकरण पूरी तरह से निशुल्क है और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस) द्वारा स्थापित मानकों को भी पूरा करता है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती संसाधन भंडार खोलने के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करने का भी प्रावधान है।

पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और फसल उत्पादन लागत को कम करने में प्राकृतिक खेती योजना मील पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू सभी वर्गों व क्षेत्रों का समग्र और समान विकास करने के लिए समुचित प्रयास कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने केन्द्र से जल आपूर्ति और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भेंट की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग को धनराशि जारी करने संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

उप-मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल को अवगत करवाया कि हालांकि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 916.53 करोड़ रुपये आवंटित करने को स्वीकृति दी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। उप-मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की पहली किश्त के पहले और दूसरे ट्रेंच की 458.26 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिनमें फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के तहत शामिल करने के लिए काफी समय से विचाराधीन हैं। इसके लिए लगभग 282.47 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 120.79 करोड़ रुपये की बीत एरिया और कुटलैहड़ परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान करने का आग्रह भी किया।

पीएमकेएसवाई के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के मामले पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

मुकेश अग्निहोत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश को भारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे राज्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उन्होंने कहा कि सर्वाधिक नुकसान कुल्लू और मनाली क्षेत्र में हुआ। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे विशेषरूप से पलचान और औट क्षेत्र के बीच बाढ़ नियंत्रण और प्रबन्धन के लिए बाढ़ प्रबन्धन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि की आवश्यकता है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की बाढ़ के नुकसान और आवश्यक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है।

केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह राज्य सरकार की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर शूरवीरों को किया नमन

शिमला/शैल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में कारगिल के शहीदों की शहादत को नमन किया। उन्होंने कारगिल शहीदों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उन शूरवीरों के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

उन्होंने कारगिल शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम सभी को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर गर्व है। उन्होंने देश की सुरक्षा कर रहे सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति आभार व्यक्त किया। कारगिल में दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा।

प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध:राजस्व मंत्री

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी व कानूनगो महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री से वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों पर विचार करने का आग्रह किया।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पटवारी व कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर में करने का निर्णय जनहित में लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश की जनता से भी सरकार को सुझाव प्राप्त हुए। प्रदेश सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण के साथ यह फैसला जनहित में लिया है।

उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो का राज्य कैडर किए जाने से उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति और उन्हें मिलने वाले भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने सिर्फ राज्य कैडर का निर्णय लिया है, जबकि भर्ती और पदोन्नति नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो आने वाले समय में नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदोन्नत होंगे।

राज्य कैडर होने से दूसरे जिलों में कई वर्षो से कार्यरत पटवारी व कानूनगो को अपने जिले में वापसी का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे उन्हें भी अपने जिले में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ सरकारी सेवाओं को छोड़कर जनहित में अधिकांश सेवाएं राज्य कैडर में की जा चुकी हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पटवारी व कानूनगो के काम बंद करने से प्रदेश की जनता के राजस्व संबंधी कई कार्य लंबित हैं, आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का दायित्व है कि वह आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। इसी के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं।

सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देकर सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया है। कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य भत्तों का भी भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महासंघ की अन्य मागों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

इस मौके पर निदेशक भू-रिकॉर्ड सीपी वर्मा, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद और अवर सचिव राजस्व सीमा सागर भी उपस्थित थी।

राज्य सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि समाज में सभी को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ऐसे वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 50 हजार रुपये से कम आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को घर के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष में 1,150 लाभार्थियों को आवास सुविधा के लिए 17.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ पेशेवर प्रशिक्षण भी दे रही है, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा उन्हें अपना उद्यम लगाने के लिए मशीनरी और उपकरण भी दिए जा रहे हैं। कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रदेश सरकार निशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि नाइलेट और सी-डेक द्वारा प्रदेश में संचालित 97 केंद्रों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा पाठयक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि और सरकारी कार्यालयों में छह माह के दक्षता प्रशिक्षण के दौरान 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। गत वित्तीय वर्ष में 3,637 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 50 हजार से कम आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को औजारों और उपकरणों की खरीद के लिए 1300 रुपये, प्रशिक्षितों को सिलाई मशीन के लिए 1800 रुपये प्रदान कर रही है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, कौशल विकास, पानी, जलक्रीड़ा गतिविधियों, स्वच्छता और सौर ऊर्जा के लिए अल्पसंख्यकों को वित्त पोषित कर रही है।

उन्होंने कहा कि काजा में संयुक्त केंद्र के निर्माण पर 12.77 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने 24.45 करोड़ की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि राज्य के हर व्यक्ति को समान अवसरों और संसाधनों की पूरी पहुंच हासिल हो।

प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को दिया जाएगा प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण:स्वास्थ्य मंत्री

शिमला। स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य रेडक्रॉस समिति के अध्यक्ष डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की गई। डॉ. शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्कूली छात्र रेडक्रॉस में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वह जूनियर रेडक्रॉस के तहत शामिल किए जाएंगे तथा उन्हें विशेषतौर पर प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे और छात्रों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी यूथ रेडक्रॉस के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदेशभर में अधिक से अधिक पौधरोपण अभियान के आयोजन पर भी बल दिया और कहा कि स्वयंसेवकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पौधरोपण स्थलों पर पौध की नियमित देखभाल हो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की देखभाल और पौधरोपण भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य व धरती के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है।

डॉ. शांडिल ने बताया कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा पीजीआई सेटेलाइट केंद्र, ऊना के नजदीक सराय भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा के टाण्डा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के समीप रेडक्रॉस द्वारा सराय भवन का निर्माण किया गया है।

डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने रेडक्रॉस द्वारा राज्य, जिला एवं उपमंडलीय स्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों को सराहा, विशेषतौर पर गत वर्ष आई आपदा के दौरान राज्य रेडक्रॉस द्वारा किए गए राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस द्वारा वर्षभर प्रदेश में स्वास्थ्य जांच शिविर, नशा निवारण शिविर, प्राथमिक उपचार शिविर, रक्तदान शिविर, रेडक्रॉस मेले, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान आदि आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न किट्स व कम्बल आदि का आबंटन, व्हील चेयर, कृत्रिम अंग और एम्बुलेंस सेवाएं आदि भी प्रदान की जाती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान रेडक्रॉस के स्वयंसेवक सदैव राहत एवं बचाव कार्यों में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की समाज में अहमियत को देखते हुए इसके द्वारा आयोजित गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने एवं स्वयंसेवकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित बजट सहित विभिन्न मुद्दों को अनुमोदित किया गया है।

बैठक में राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेडक्रॉस समिति के महासचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त सिरमौर एवं जिला रेडक्रॉस समिति के अध्यक्ष सुमित खिमटा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी सहित सभी जिला रेडक्रॉस समितियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

परवाणु में भारतीय मानक ब्यूरो ने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 52 प्रतिभागियों ने भारतीय मानक ब्यूरो की परवाणु ब्रांच कार्यालय द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यशाला में भाग लिया।

परवाणु ब्रांच कार्यालय के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नायक ने प्रतिभागियों को भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ब्यूरो देश में गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्य करता है। भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण-पत्र उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित उत्पाद की गारंटी देता है।

संयुक्त निदेशक शिव प्रकाश ने ब्यूरो के विशेष मापदंडों, उत्पादों के मूल्यांकन और अनिवार्य पंजीकरण योजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क के दुरूपयोग रोकने के लिए बीआईएस एक्ट-2016 के प्रावधानों को भी विस्तारपूर्वक बताया।

निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राघव शर्मा, अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज नीरज चांदना, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण विकास कल्याणी गुप्ता ने कार्यशाला में भाग लिया।

हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024

तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी।

मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिक्ति, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई, से 31 अक्तूबर, 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मण्डल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा परवाणु में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैठक में सुबाथू उप-मण्डल के क्षेत्राधिकार को अर्की मण्डल से धर्मपुर मण्डल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मण्डलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में लोगों की सुविधा के लिए प्रागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खण्डों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्यन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला कांगड़ा के टाण्डा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में योगा इंस्ट्रक्टर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खण्ड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 01 अगस्त, 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप-समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह उप-समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा होंगे। यह उप-समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी।

बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला सप्ताह में सात दिन के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक और किसान विरोधी बताया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट-2024 पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे असमानतापूर्ण बजट करार दिया है। उन्होंने चिंता के कई प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला और राज्य की व्यापक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल संशोधन का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट एक बार फिर देश के ज्वलंत मुद्दों, विशेषकर बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती कीमतों को संबोधित करने में विफल रहा है। हालांकि राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए मौजूदा आवंटन 1.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये करना एक स्वागत योग्य घोषणा है लेकिन लागत अक्षमताओं के कारण इसके साथ जुड़ी कठिन शर्तें हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हालांकि बजट अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश में पिछले साल मानसून के दौरान हुए भारी नुकसान के कारण पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए प्रदेश को बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता का उल्लेख किया गया है, लेकिन दी जाने वाली सटीक राशि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हमें उम्मीद थी कि हिमाचल को भी असम, सिक्किम और उत्तराखंड की तर्ज पर सीधी सहायता दी जाएगी। राज्य को आशा है कि हिमाचल को यह सहायता केंद्र सरकार के पास लंबित 9042.66 करोड़ रुपये के पीडीएनए दावों के अतिरिक्त होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सेब उत्पादक गंभीर वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं। बजट में उनके संघर्षों को कम करने या सेब पर आयात शुल्क कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, जो हिमाचल के सेब उत्पादकों को जरूरी राहत प्रदान कर सकता था। उन्होंने कहा कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार के मुद्दे को संबोधित करने में यह बजट विफल रहा है। आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत रेल नेटवर्क आवश्यक है, फिर भी इसे बार-बार नजरअंदाज किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। इसके कारण हो रहे वार्षिक घाटे को हमारा राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस नुकसान को कम करने और राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। बजट में इस तरह के पैकेज का अभाव एक महत्वपूर्ण झटका है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखु ने कहा के यह गरीब विरोधी बजट है और भविष्योन्मुखी नहीं है। यह पूरी तरह अवसरवादी बजट है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए खास तौर पर आयकर स्लैब और छूट के मामले में पर्याप्त कर राहत की उम्मीद थी। लेकिन बजट इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं में निराशा है।

उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के मुद्दों जैसे अपर्याप्त समर्थन मूल्य और आधुनिक कृषि पद्धतियों व बुनियादी ढांचे के लिए अपर्याप्त धन को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों का भी अभाव है। केंद्रीय बजट-2024 भारत की जरूरत के हिसाब से समावेशी और सहायक वित्तीय योजना नहीं बन पाया है। यह बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और बढ़ती असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कई अन्य राज्यों की तरह एक ऐसे बजट के परिणामों से जूझ रहा है जो आम लोगों की तुलना में अमीरों को प्राथमिकता देता है। यह एक ऐसे बजट के लिए सही समय है जो वास्तव में सभी नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाता है और समाज के हर वर्ग के लिए समान विकास और समृद्धि सुनिश्चित करता है।

पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा और बेहतर सुविधाएं की जा रहीं सुनिश्चित:मुख्यमंत्री

वर्ष 2024 की पहली छमाही में हिमाचल पहुंचे एक करोड़ से अधिक सैलानी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद में ज़बरदस्त उछाल देखने में आया है। प्रदेश ने वर्ष 2024 की पहली छमाही में एक करोड़ से अधिक सैलानियों का आतिथ्य सत्कार किया। हिमाचल की मनोहारी वादियों, स्वच्छ वातावरण और प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर सुविधाओं के फलस्वरूप इस साल जून माह के अन्त तक रिकॉर्ड 1,00,87,440 पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर पहुंचे।

प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति पर्यटकों से गुलजार हैं। इस अवधि में सर्वाधिक पर्यटक कुल्लू और शिमला ज़िलों में उमड़े। कुल्लू ज़िले की 4,73,737 और शिमला ज़िले की 4,48,392 सैलानियों ने यात्रा की। प्रदेश में जुलाई माह में भी पर्यटकों का आगमन निरन्तर जारी है। प्रदेश की अधिकतर सड़कें पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए खुली हैं और पर्यटक हिमाचल की नैसर्गिक सुन्दरता को निहारने के लिए प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटकों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के अधिकांश मार्ग यातायात के लिए खुले हैं। खराब मौसम के कारण प्रदेश की कुछ सड़कें प्रभावित हुई थीं, लेकिन वर्तमान में पर्यटकों और आमजन के लिए अधिकतर सड़कें खोली जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में हज़ारों की संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की और इस वर्ष के अन्त तक पर्यटकों की संख्या दो करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलानी प्रदेश के विभिन्न स्थलों की यात्रा से संबंधित जानकारी संबंधित ज़िला प्रशासन व पुलिस विभाग के हेल्पलाइन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटकों की सुगम एवं सुरक्षित यात्रा तथा उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सैलानियों की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग बाधित सड़कों को बहाल करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। पर्यटन एवं नागरिक उड्यन विभाग पर्यटकों को समय-समय पर विशेष सड़क मार्गों पर यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ज़िला प्रशासन और हिमाचल पुलिस द्वारा सड़कों की स्थिति संबंधी जानकारी निरन्तर उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

अपने संसाधनों से नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी राज्य सरकार

➤ केंद्र से मिली 30 करोड़ रुपये की मदद लौटाने का निर्णय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपये लौटाने निर्णय

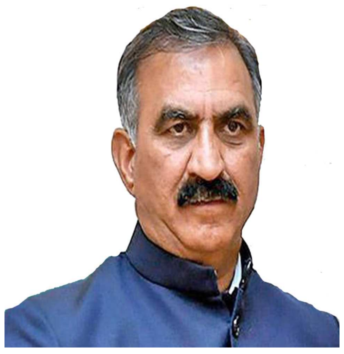

लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि एक रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के अलावा दस वर्षों तक पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी।

मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को एनएसजीएसटी के कारण प्रत्यक्ष नुकसान होता। इसलिए राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का निर्णय लिया, जिससे जमीन और अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले 5-7 वर्षों में 500 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है। अब राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले उद्योगों को अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देगी। इन संसाधनों पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न मोर्चों पर हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसी दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्वयं बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की राशि नहीं लौटाते हैं तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन प्रदान करने पड़ेंगे, जिससे राज्य के खजाने पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा और सरकार को राजस्व को घाटा होगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अब तक 74.95 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं और प्राथमिकता पर मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। श्री सुक्खू ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने जिला ऊना के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क में किसी भी प्राइवेट एजेंसी की मदद नहीं लेने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये अपने संसाधनों से प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकार क्लस्टर विकास योजना के तहत सिडबी से ऋण लेगी। अब परियोजना में फेरबदल करते हुए 25 प्रतिशत भूमि विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए और 75 प्रतिशत अन्य रणनीतिक उद्योगों के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक पार्क को हिमाचल प्रदेश में अत्याधुनिक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए आय का नियमित स्रोत बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और उद्योगपतियों को उनके कारोबार में हर संभव सहायता दी जा रही है। आने वाले समय में भी राज्य सरकार उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रखेगी।

वित्तीय से ज्यादा

......पृष्ठ 1 का शेष

खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब सरकार आम आदमी को मिली हुई सुविधाओं पर किसी भी तर्क से कैंची चला रही है तो उसी अनुपात में सबसे पहले अपने खर्चों पर कटौती करनी होगी। आज यह सवाल उठ रहा है कि सरकार को कैबिनेट रैंक में इतने सलाहकारों और दूसरे लोगों की क्या आवश्यकता पड़ गई है। क्या सरकार बता पाएगी कि किस सलाहकार ने क्या नीतिगत मूल्यवान सलाह दी है जिससे सरकार को अमुक लाभ हुआ है। आने वाले समय में आरटीआई में यह सवाल पूछे गये तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि राहतों में कटौती और भारी भरकम कर्ज आपस में स्वत: विरोधी हैं। आज के हालात में वित्तीय से ज्यादा विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे हालत में छवि सुधारने के प्रयास बेमानी हो जाएंगे यह तय है।

महिला आरक्षण कानून जल्द लागू किया जाये:जैनब चंदेल

शिमला/शैल। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने पर अब टालमटोल कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि महिला आरक्षण कानून जल्द लागू किया जाये। इसमें ओबीसी, पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए।

राजीव भवन में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी दलों के दबाव में भाजपा ने देश में उस समय चुनावों को देखते हुए इसका लाभ लेने के लिये बिल पास तो कर दिया परन्तु अब उसे लागू करने के लिये कोई भी गंभीर प्रयास नही किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसे लागू किया जाये।

जैनब चंदेल ने बताया कि 29 जुलाई को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के आहवान पर प्रदेश महिला कांग्रेस की सैंकड़ो

महिलाएं दिल्ली के जंतरमंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़े धरना प्रदर्शन में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस महिला आरक्षण, बढ़ती महंगाई व महिलाओं को सुरक्षा व उनके अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को संसद व विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नही मिलेगा तब तक इनके साथ न्याय नही होगा। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण में महिलाओं की उचित भागेदारी बहुत ही आवश्यक है।

जैनब चंदेल ने केंद्र सरकार से महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं के खाते में हर साल एक लाख एकमुश्त या हर माह 8500 रुपए इनके खाते में डालने की मांग की है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों के समय महिलाओं को वोट बैंक अपनी ओर आकर्षित करने के लिये बड़े बड़े लोक लुभावन नारे देती है और चुनावों के बाद भूल जाती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया था पर आज वह इस पर भी खामोश बैठी है। देश में महिलाओं पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहे है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा के शासनकाल में मध्यप्रदेश में बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाढ़ने का प्रयास किया गया जो बहुत ही दुखदाई है। महाराष्ट्र में बलात्कार की पीड़ित एक महिला को न्याय नही मिल पा रहा है।

जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में दिन रात का अन्तर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी अन्याय के खिलाफ विशेषकर महिलाओं के अधिकारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नही मिल जाता।

प्रैस वार्ता में सत्या वर्मा, कमलेश ठाकुर व विन्नी शर्मा भी जैनब चन्देल के साथ मौजूद थी।